सांध्य दैनिक

4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in | www.facebook.com/4pmnewsnetwork | @Editor_SanjayS | YouTube @4pm NEWS NETWORK

• वर्षः 12 • अंक 92 पृष्ठः 8 • लखनऊ, शुक्रवार 8 मई, 2026

मूल्य ₹ 3/-

किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपके कुर्बानी का सम्मान करे।

–ब्रह्म कुमारी शिवानी

घर में 5 मैचों बाद लखनऊ की... 7 | सजा पूरी फिर भी कैद, प्रशासनिक... 3 | भाजपा ने सबसे ज्यादा लोकतंत्र... 2

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की आहट!

गवर्नर ने टीवीके प्रमुख के सरकार गठन के दावे को दो बार ठुकराया

» स्थिर सरकार न बन पाने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं गवर्नर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त उबलते ज्वालामुखी की तरह खड़ी है। सरकार नहीं बन रही, बहुमत साबित नहीं हो रहा, विधायक रिसॉर्ट में बंद हैं और राजभवन सत्ता के सबसे बड़े कंट्रोल रूम में बदलता दिखाई दे रहा है। टीवीके प्रमुख विजय थलापति सरकार बनाना चाहते हैं। दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर हैं। लेकिन राज्यपाल ने उनका दावा ठुकरा दिया है। वजह साफ है कि राजभवन पहले समर्थन देने वाले विधायकों की पूरी सूची चाहता है ताकि लोकतंत्र को विधायकों की खरीदो-फारोख्त से बचाया जा सके।

यानी अब सिर्फ बहुमत का दावा काफी नहीं रहा अब विश्वसनीय बहुमत साबित करना होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ संवैधानिक सतर्कता है या फिर राजनीति का नया पॉवर सेंटर अब विधानसभा नहीं बल्कि राजभवन बन चुका है? तमिलनाडु में तेजी से बदलते समीकरणों के बीच एआईएडीएमके और तमिलनाडु के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। जो पार्टीयां कुछ दिन पहले तक बैकफुट पर दिखाई दे रही थी वह अब सत्ता के नए गणित में एंट्री मार चुकी है। होटल, रिसॉर्ट, बंद कमरे, गुप्त बैठकों और फोन कॉल्स के बीच सत्ता का ऐसा खेल चल रहा है जिसमें जनता सिर्फ टीवी स्क्रीन पर तमाशा देख रही है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी तरह सरकार बन भी गई तो चलेगी कैसे? क्या बिना स्थिर बहुमत के बनी सरकार पांच साल टिक सकती है? ऐसे राजनीतिक जानकार तो यही कह रहे है कि शनै शनै तमिलनाडु राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर हो रहा है।

फ्लोर पर बहुमत साबित करना चाहते हैं विजय जोसफ यही परपंरा भी रही है

तमिलनाडु क्यों महत्वपूर्ण है?

तमिलनाडु सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली केंद्र है। यहां की राजनीति लंबे समय से डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन विजय थलापति की एंट्री ने पूरे समीकरण को हिला दिया है। अगर टीवीके सत्ता के करीब पहुंचती है, तो यह तमिल राजनीति में तीसरे बड़े ध्रुव का उदय होगा। यही कारण है कि हर दल इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है।

क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है?

हालांकि टीवीके सरकार बनाने के बेहद करीब है और कार्यवाहक सीएम स्टालिन बयानों में तो यही कह रहे है कि वह विजय थलापति को सरकार बनाने का मौका देना चाहते हैं। बयान तो ठीक है लेकिन बयान के भीतर की कूटनीति उस समय सर्वजनिक हो जाती है जब स्टालिन अंदर ही अंदर सरकार बनाने की स्टालिन की कोशिशें बाहर आ जाती है। जानकार साफ कह रहे हैं कि जब तक डीएमके या एआईएडीएमके का बड़ा धड़ा टूटकर बाहर नहीं आता तब तक कोई स्थिर सरकार संभव नहीं। यानी असली लड़ाई चुनाव जीतने की नहीं विधायकों को बचाने और तोड़ने की है।

> “सिर्फ बहुमत का दावा काफी नहीं रहा अब विश्वसनीय बहुमत साबित करना होगा।”

सबसे बड़ी पार्टी बनाम बहुमत गठबंधन

कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बहुमत का दावा पेश किया था। इसके बावजूद राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए और इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त समय देकर विधायकों की तोड़फोड़ की कोशिश की गई।

परंपरा कुछ और लेकिन गवर्नर की शक्तियां असीमित

देश पहले भी ऐसे राजनीतिक विवाद देख चुका है। महाराष्ट्र में 2019 के घटनाक्रम के दौरान सुबह-सुबह राष्ट्रपति शासन हटाकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिलाई गई थी। जिस पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए थे। कर्नाटक, गोवा और मणिपुर में भी राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवैधानिक बहस छिड़ चुकी है। ऐसे में तमिलनाडु के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार गठन की प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी। तमिलनाडु इस वक्त सिर्फ राजनीतिक संकट में नहीं है बल्कि वह भारतीय संघीय ढांचे की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है।

गोवा और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी सत्ता से बाहर

गोवा और मणिपुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन बीजेपी ने तेजी से गठबंधन तैयार किया और राज्यपाल ने उसे सरकार बनाने का मौका दे दिया। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या सरकार बनाने का पहला अधिकार सबसे बड़ी पार्टी को मिलना चाहिए या बहुमत गठबंधन को?

सूरज निकलने से पहले बदल गई सरकार

भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित घटनाक्रमों में महाराष्ट्र का मामला हमेशा याद किया जाएगा। चुनाव के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच अचानक राष्ट्रपति शासन हटाया गया और सुबह-सुबह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तथा अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। पूरे देश को यह खबर तब मिली जब अधिकांश लोग नींद से जाग भी नहीं पाए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राजभवन ने असाधारण तेजी दिखाते हुए सत्ता गठन में भूमिका निभाई। हालांकि बाद में यह सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकी और गिर गई, लेकिन इस घटना ने राज्यपाल की भूमिका पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी।

तेजी से गहरा रहा है अनिश्चितता का माहौल

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल गहराता जा रहा है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद सरकार गठन का संकट पैदा हो गया है। टीवीके प्रमुख विजय थलापति ने सरकार बनाने का दावा पेश किया लेकिन राज्यपाल ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। राजभवन ने विजय से उन विधायकों की सूची मांगी जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यह मांग अपने आप में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। टीवीके चाहती थी कि उन्हें पहले फ्लोर टेस्ट का मौका मिले ताकि विधानसभा में बहुमत साबित किया जा सके। लेकिन राज्यपाल का रुख ज्यादा सतर्क और कठोर दिखाई दिया। इसी बीच एआईएडीएमके भी अचानक सक्रिय हो गई। पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए पड़ोसी राज्य के रिसॉर्टों में भेजना शुरू कर दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन असली समस्या सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है। असली सवाल यह है कि स्थिरता कहां से आएगी? अगर किसी छोटे अंतर से सरकार बन भी जाती है तो क्या वह लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या हर हफ्ते विश्वास मत और बगावत की आशंका बनी नहीं रहेगी? यही कारण है कि अब राष्ट्रपति शासन की चर्चा भी तेज हो गई है। संविधान के मुताबिक अगर कोई भी दल स्थिर सरकार नहीं बना पाता और प्रशासनिक संकट गहराने लगता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में इस्तीफों से गिर गई सरकार

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार तब गिर गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह लोकतांत्रिक जनादेश नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस था। हालांकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक पुनर्संरचना बताया।

भाजपा ने सबसे ज्यादा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया : अखिलेश यादव

» टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी से मिले सपा प्रमुख

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और भाजपा पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। यह मुलाकात भाजपा की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की रणनीति के तहत हुई है।

अखिलेश ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से कोलकाता स्थित टीएमसी अध्यक्ष के आवास पर मुलाकात की। टीएमसी के आधिकारिक सूत्रों ने अखिलेश यादव से कहा कि दीदी, आप हारी नहीं हैं। उन्होंने आगे बताया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के दौरान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभिषेक से कहा,आप सभी ने कितनी सराहनीय लड़ाई लड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में जो हुआ है, उससे लोकतंत्र को नष्ट करने का रास्ता मिल गया है। शायद ही किसी ने लोकतंत्र को इतना नुकसान पहुंचाया हो जितना भाजपा ने। वे कभी किसी महिला के उत्थान को नहीं देख सकते। यहां मतदान तो हुआ है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से ज्यादा दबाव में आकर मतदान किया है।

विपक्षी एकता के प्रति अपना समर्थन

अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने का संकल्प लिया है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया और टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की सीटें घटकर 80 रह गईं।

ममता बनर्जी सिर्फ नाराजगी जता रही थीं : तारिक अनवर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि ममता बनर्जी ने एक तरह से विरोध जाहिर किया था। वो भी जानती थीं कि हमारी सरकार चुनकर नहीं आई है तो सरकार में बने रहना असंभव है।

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, ममता बनर्जी ने एक तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि जिस तरह से वहां चुनाव हुआ और इसमें धांधली हुई, जिस तरह से तमाम एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उसको लेकर वो अपनी नाराजगी जता रहीं थीं। इस ज्यादा वो कुछ नहीं था, एक प्रकार का प्रोटेस्ट था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने ममता बनर्जी के कैबिनेट को भी बर्खास्त कर दिया है। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया है। लोकभवन, कोलकाता की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा भंग करने का आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी गलती हुई : उमर

» बोले सीएम- हमें इंतज़ार करके देखना होगा कि देश के बाकी हिस्सों में क्या होता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी गलती हुई है और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। वोटर लिस्ट से बहुत सारे वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हम चुनावों के बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे। अब सुनवाई करने का क्या फ़ायदा? चुनाव तो खत्म हो चुके हैं और उन लोगों को वोट डालने का मौका ही नहीं मिला।

अगर बीजेपी जीतना चाहती थी, तो वह जीत गई। हमें इंतज़ार करके देखना होगा कि देश के बाकी हिस्सों में क्या होता है? जम्मू कश्मीर के शोपियां में जो मदरसा सील हुआ उस पर उमर अब्दुल्ला खामोश हैं, आरोप पर सीएम ने कहा,मैं किसी दूसरी पार्टी के कहने के मुताबिक अपना काम नहीं करता। मुझे जब कुछ कहना होता है तो मैं कहता हूं। न मैं खामोश हूं, न मेरी हुकूमत खामोश है। जहां जहां मुद्दे आते हैं, जिन पर हमें बोलना होता है, हम बोलते हैं। या तो हुकूमत की तरफ से या तंजीम की तरफ से। क्या कैबिनेट में कई फेरबदल होगी, इस सवाल पर सीएम अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए मीडिया से कहा, आप लोगों को इतनी फिक्र क्यों है, जब करना होगा तो कर लेंगे।

नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों को छोड़ने की बातें बेबुनियाद

कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर सीएम अब्दुल्ला ने कहा, गर कुछ विधायक छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे होते तो मैं यहां कार्यक्रम में बैठा होता? ये बेबुनियाद बाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कहने के मुताबिक राज्यसभा में उनकी मदद की. ये हम नहीं कह रहे। राइट टू इनफॉर्मेशन के तहत साबित हुआ. नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा विधायक नहीं है तो तंजीम को छोड़कर बीजेपी की मदद करने के लिए निकले।

फारूक अब्दुल्ला की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी उम्मीद

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इन परिणामों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कई प्रमुख विपक्षी नेता इन नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल्ला ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन नेताओं सहित अन्य विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह जता रहे हैं। विपक्षी खेमे में चुनाव परिणामों की वैधता को लेकर व्यापक असंतोष देखा जा रहा है। यह असंतोष लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी तंत्र में विश्वास से जुड़ा है। फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि ये सभी नेता अब इस पूरे मामले को देश के सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना अंतिम और निष्पक्ष फैसला सुनाएगा। यह कदम चुनाव संबंधी विवादों के समाधान के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है।

विपक्षी नेताओं का मानना है कि न्यायिक समीक्षा से ही सच्चाई सामने आ सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद से ही विपक्षी दलों में बेचैनी है। कई नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से इन नतीजों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि चुनाव प्रक्रि या में कुछ अनियमितताएं हुई हैं। इन चिंताओं में मतदान की प्रक्रिया, वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा से जुड़े पहलू शामिल हैं। विपक्षी दल इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण और न्याय की मांग कर रहे हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट चुनावी विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है जो संवैधानिक मामलों की व्याख्या करता है। चुनाव संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर वह निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान न्यायपालिका पर उनके विश्वास को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करेगा।

सपा के कई नेता सुभासपा में शामिल ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में टूट हुई है। सपा के 30 पदाधिकारी पार्टी को छोड़ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) में शामिल हो गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर की मौजूदगी में सभी नेताओं को सदस्यता दिलाई गई।

उन्होंने कहा कि पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। पार्टी में शामिल होने वालों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम प्रमुख रहे। इसके अलावा बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद नाजिम अंसारी, युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष खालिद सैफी, राष्ट्रीय सचिव अयूब अंसारी, प्रदेश प्रभारी कारी लाइक अंसारी, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुफ्ती मेहर आलम कासमी अंसारी, सलीम अंसारी, मोहम्मद अय्यूब अंसारी, मोहम्मद रिजवान, मो. नईम, कल्लन सैफी, शकील अहमद, उमर, जहीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, मुन्तयाज, पदम प्रकाश, अंकित कुमार, मोहम्मद फुरकान, इन्जयामुल हक, बदर जमील, सद्दन खान, नवेद आलम, अनीस अहमद, वकील अहमद (बिजनौर), वकील अहमद (लखनऊ) कारी सलमान और पूर्व प्रभारी बलराज प्रजापति शामिल रहे। इनमें कई लोग दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, शाहदरा, प्रतापगढ़, अमरोहा और लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए नारा राजनीतिक जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीडीए का मतलब पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश है।

राज ठाकरे के विरोध के आगे झुकी भाजपा सरकार

» महाराष्ट्र के अधिकारियों के लिए अब हिंदी की परीक्षा जरूरी नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र के अधिकारियों के लिए अब हिंदी की परीक्षा जरूरी नहीं, राज ठाकरे के विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया। महाराष्ट्र के मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि राजपत्रित और गैर-राजपत्रित अधिकारियों के लिए हिंदी भाषा परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी गई है यह कदम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के विरोध के बीच उठाया गया है।

उदय सामंत ने कहा, मैंने प्रधान सचिव (मराठी भाषा विभाग) किरण कुलकर्णी से बात की। परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि वह इस बात का पता लगाएंगे कि परीक्षा की वास्तव में आवश्यकता है या नहीं। मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने कहा भविष्य में, यदि हमें लगता है कि परीक्षा अनावश्यक है, तो हम इसे आयोजित नहीं करने का निर्णय लेंगे।

हिंदी थोप रही है सरकार : मनसे नेता संदीप देशपांडे

दूसरी ओर, मनसे की मुंबई इकाई के प्रमुख संदीप देशपांडे ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार द्वारा हिंदी थोपने के निर्णय की निंदा करती है. देशपांडे ने चेतावनी दी कि परीक्षा केंद्रों के बाहर होने वाली गड़बड़ी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

सजा पूरी फिर भी कैद प्रशासनिक विफलता की हद

चीनी नागरिक वांग गोउ जून के मामले पर सवाल

» इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैदर रिजवी की पहल लाई रंग

» दो महीने से अधिक समय से अवैध रूप से बंद विदेशी नागरिक को मिली रिहाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ/लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की जिला जेल लखीमपुर खीरी से सात मई को एक ऐसे विदेशी नागरिक की रिहाई हुई, जिसकी सजा लगभग ढाई महीने पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन वह इसके बावजूद जेल में बंद रहा। चीन के नागरिक वांग गोउ जून का यह मामला अब केवल एक व्यक्ति की रिहाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह भारतीय प्रशासनिक तंत्र, जेल व्यवस्था, विधिक सहायता प्रणाली और संवैधानिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के अधिवक्ता सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी के लगातार प्रयासों, प्रशासन को भेजे गए प्रतिवेदनों, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दायर आवेदन, राज्य सूचना आयोग में शिकायत और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अंततः 7 मई 2026 को वांग गोउ जून को जिला कारागार लखीमपुर खीरी से रिहा किया गया। जेल प्रशासन ने पुष्टि की कि उसे दिल्ली ले जाया जा रहा है, जहां से वह अपने गृह प्रांत गुआंगडोंग, चीन के लिए रवाना होगा। यह पूरा मामला इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसमें किसी न्यायालय ने उसको आगे की हिरासत का आदेश नहीं दिया था। उसकी सजा पूरी हो चुकी थी। फिर भी वह जेल में बंद रहा। सवाल यह है कि आखिर क्यों?

वांग गोउ जून, चीन नागरिक

सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी, अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ)

सजा खत्म होने के बाद भी जेल में बंद रहा कैदी

17 फरवरी 2026 के बाद भी वांग गोउ जून जिला कारागार लखीमपुर खीरी में बंद रहे। उनके खिलाफ कोई नया मुकदमा नहीं था, कोई नया न्यायिक आदेश नहीं था और न ही किसी अदालत ने उनकी निरंतर हिरासत को वैध ठहराया था। जेल प्रशासन ने बाद में मीडिया को बताया कि उन्हें अस्थायी निरोध केंद्र में रखा गया था। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा कोई अस्थायी निरोध केंद्र न्यायालय नहीं होता और न ही वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का वैधानिक अधिकार रखता है। यही बिंदु इस पूरे प्रकरण को गंभीर बनाता है।

अपील में घटी सजा, लेकिन जेल से नहीं मिली रिहाई

वांग गोउ जून ने इस फैसले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (नवीन), लखीमपुर खीरी की अदालत में चुनौती दी। आपराधिक अपील संख्या 19/2025 पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 17 जनवरी 26 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने सजा को पांच वर्ष के कठोर कारावास से घटाकर तीन वर्ष के साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित माना जाएगा। क्योंकि वांग गोउ जून 17 फरवरी 23 से लगातार हिरासत में थे, इसलिए उनकी वैधानिक सजा 17 फरवरी 26 को समाप्त हो गई थी। कानून के अनुसार उसी दिन या उसके तुरंत बाद उन्हें रिहा किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

आरटीआई का सहारा, लेकिन 48 घंटे में नहीं मिली सूचना

25 अप्रैल 26 को अधिवक्ता रिजवी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 205 की धारा 7(1) के अंतर्गत जिला कारागार, लखीमपुर खीरी के जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि यह मामला जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है, इसलिए सूचना 48 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। सूचना न मिलने के बाद अधिवक्ता रिजवी ने 30 अप्रैल 26 को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में शिकायत दाखिल की। उन्होंने आरटीआई अधिनियम की धारा 18 और 15(4) के अंतर्गत कार्रवाई की मांग करते हुए जन सूचना अधिकारी पर धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये तक के जुर्माने की मांग की। उनका कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला अस्पष्ट और अवैध है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सजा पूरी हो चुकी है, उसे केवल प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण जेल में नहीं रखा जा सकता।

बार और अधिवक्ताओं से की गई अपील

अधिवक्ता रिजवी ने इस प्रकरण को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि पूरे विधि समुदाय से अपील की है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को जेलों का निरीक्षण करना चाहिए, ऐसे कैदियों की पहचान करनी चाहिए जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, आरटीआई का प्रयोग करना चाहिए।

अखबार की खबर से सामने आया मामला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के अधिवक्ता एस.एम. हैदर रिजवी को इस मामले की जानकारी 9 अप्रैल 2026 को दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार से मिली। समाचार का शीर्षक था – चीनी नागरिक की सजा पूरी, अब लौटेगा अपने वतन समाचार में जेल अधीक्षक का यह बयान था कि वांग गोउ जून ने अपनी सजा पूरी कर ली है और उसे सुरक्षा व्यवस्था के साथ रिहा किया जाना था। रिहा किया जाना था – इस वाक्य ने अधिवक्ता रिजवी को विचलित कर दिया। उन्होंने मामले के न्यायिक अभिलेखों का अध्ययन किया और पाया कि वास्तव में उस व्यक्ति की सजा समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वह जेल में बंद था।

प्रशासन से लेकर दूतावास तक भेजे गए प्रतिवेदन

9 अप्रैल 2026 को अधिवक्ता रिजवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी और पुलिस अधीक्षक को विस्तृत प्रतिवेदन भेजे। इनकी प्रतियां केंद्रीय गृह सचिव, विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास को भी भेजी गईं।

बिना फीस, बिना वकालतनामा शुरू की कानूनी लड़ाई

एस.एम. हैदर रिजवी का कहना है कि उनका वांग गोउ जून से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। उन्होंने कभी उसका मुकदमा नहीं लड़ा और न ही इस मामले में कोई पारिश्रमिक लिया। उन्होंने केवल संवैधानिक दायित्व और मानवीय आधार पर यह प्रयास शुरू किया। उन्होंने कहा–मैंने उनका प्रतिनिधित्व कभी नहीं किया। मेरा इस परिणाम में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। मैंने केवल विवेक और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से प्रेरित होकर यह प्रयास किया।

डीएलएसए और एसएलएसए पर भी सवाल

इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) की भूमिका पर भी प्रश्न उठे हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार इन संस्थाओं का दायित्व है कि वे उन कैदियों की पहचान करें जो,रिहाई के पात्र हैं, जमानत पाने के योग्य हैं या जिन्हें कानूनी सहायता नहीं मिल रही। लेकिन वांग गोउ जून के मामले में ऐसा कोई प्रभावी हस्तक्षेप सामने नहीं आया।

विदेश मंत्री और चीनी राजदूत को भी भेजा पत्र

जब प्रारंभिक प्रतिवेदनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो 23 अप्रैल 2026 को अधिवक्ता रिजवी ने सीधे भारत सरकार के विदेश मंत्री को दक्षिण ब्लॉक, नई दिल्ली में विस्तृत प्रतिवेदन भेजा। इसकी प्रतियां चीन के राजदूत महामहिम जू फेइहोंग सहित संबंधित मंत्रालयों को भी भेजी गईं।

यह अकेला मामला नहीं

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई एकमात्र मामला नहीं है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार भारतीय जेलों में हजारों विदेशी नागरिक बंद हैं। इनमें से कई ऐसे हो सकते हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी हो लेकिन निर्वासन या प्रशासनिक प्रक्रिया लंबित होने के कारण वे जेलों में बने हुए हों। सिर्फ विदेशी ही नहीं, कई भारतीय कैदी भी ऐसी प्रक्रियागत देरी के कारण अतिरिक्त हिरासत झेलते हैं।

सीमा पार करते समय हुई गिरफ्तारी

वांग गोउ जून, पुत्र वांग डोंग जियो, चीन के गुआंगडोंग प्रांत के निवासी हैं। उन्हें 17 फरवरी 2023 को भारत-नेपाल सीमा पर स्थित गौरीफंटा चेकपोस्ट पर शस्त्र सीमा बल (SSB) ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के नेपाल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। उनके खिलाफ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धाराओं 3 और 12 तथा विदेशी

अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत अपराध संख्या-4/2023 दर्ज किया गया। बाद में विवेचना के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 121 और 121 भी जोड़ी गई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी की अदालत में हुई। 20 मार्च 25 को अदालत ने वांग गोउ जून को विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया।

सजा पूरी होना मतलब ऋण चुक जाना

रिजवी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने यदि कानून का उल्लंघन किया है और उसकी निर्धारित सजा पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद उसकी स्वतंत्रता को प्रशासनिक जड़ता की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा– विधिवत भोगी गई सजा एक पूर्णतः चुका दिया गया ऋण है। लगातार प्रतिवेदनों, कानूनी दबाव, मीडिया रिपोर्ट और आरटीआई कार्यवाही के बाद 7 मई 26 को वांग गोउ जून को रिहा कर दिया गया। जेल प्रशासन ने पुष्टि की कि उसे दिल्ली ले जाया जा रहा है और वहां से वह चीन लौटेगा। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल एक व्यक्ति की रिहाई नहीं, बल्कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सामने खड़ा एक गंभीर आईना है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

क्या मरती जा रही सिस्टम का मानवीय संवेदना!

> “ बहन की मौत का सबूत देने के लिए कब्र खोदकर उसके कंकाल को बैंक की चौखट पर रखने वाले जीतू के लिए 19300 रुपए बड़ी रकम थी। बहन की मौत के बाद उसके खाते की रकम जीतू को जीवनयापन का बड़ा सहारा नजर आ रही थी। एक अनपढ़, गरीब व कानून-कायदों से अनजान जीतू जैसे कई लोगों को इस देश में आए दिन दस्तावेजी सबूतों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पिछले दिनों ओडिशा से एक बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर आई। उस तस्वीर उस सिस्टम और और उन लोगों की कलई खोल दी जो कहते है सब चंगा है। सरकारें दावा करतीं हैं की सरकारी तंत्र आम आदमी के साथ खड़ा है। पर ओडिशा की यह तस्वीर क्यों उभरी। ये चित्र तो ये सवाल उठा रहा कि क्या मरती जा रही सिस्टम का मानवीय संवेदना। बतादें अपनी मृत बहन के बैंक खाते में जमा रकम निकलवाने के लिए ओडिशा के गांव में आदिवासी युवक जीतू मुंडा ने जो कदम उठाया वह गरीब की बेबसी, सिस्टम की बेरुखी और कानून-कायदों की पालना से जुड़ी संवेदनहीनता का जीता-जागता उदाहरण है। बहन की मौत का सबूत देने के लिए कब्र खोदकर उसके कंकाल को बैंक की चौखट पर रखने वाले जीतू के लिए 19300 रुपए बड़ी रकम थी। बहन की मौत के बाद उसके खाते की रकम जीतू को जीवनयापन का बड़ा सहारा नजर आ रही थी। एक अनपढ़, गरीब व कानून-कायदों से अनजान जीतू जैसे कई लोगों को इस देश में आए दिन दस्तावेजी सबूतों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है।

चिंता की बात यह है कि सिस्टम से जुड़े लोग ऐसी स्थिति में मदद करने के बजाय नियमों के ऐसे जंजाल में फंसा देते हैं कि वह लाचारी में कोई भी अप्रिय लगने वालाकदम उठाने को मजबूर हो जाता है। बैंक में जमा रकम निकालने के लिए उठाया गया यह कदम किसी एक व्यक्ति से जुड़ी त्रासदी ही नहीं है बल्कि उस समूचे सिस्टम को आईना दिखाने वाली घटना है, जो जरूरतमंदों को उसके हक से वंचित करने में ही अपनी उपलब्धि मानता है। इस प्रकरण में भी बैंक के जिम्मेदार लोगों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मदद की राह निकालने के बजाय नियम-कायदों की ऊंची दीवारें खड़ी कर दीं। यह बैंकों का वही सिस्टम है, जो रसूखदारों के लिए नियमों को लचीला बनाने में पल भर की देर नहीं लगाता। बैंक के ये ही अधिकारी कहीं व्यवस्था को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो कहीं खंजर की तरह। यह सच है कि दस्तावेजी सबूतों से जुड़े नियम-कायदे किसी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बने हैं। अहम सवाल यह है कि क्या ऐसे नियमों का उद्देश्य किसी लाचार को परेशान करना भर ही होना चाहिए। जीतू मुंडा के इस लाचारी भरे कदम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसे मदद की राह खुली जरूर है। घटना पर लीतापोती के प्रयासों में हो सकता है कि बचाव में जीतू की मानसिक स्थिति पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएं।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

अंतरिक्ष में चीनी-अमेरिकी संघर्ष के बीच भारत

पुष्परंजन

बीते बुधवार को कांग्रेस की एक सुनवाई में अमेरिकी सांसदों को बताया गया, कि चीन, अमेरिका के लिए 'अंतरिक्ष में सबसे बड़ा खतरा और प्रतिस्पर्धी' है, जो अपनी खगोलीय क्षमताओं का इस्तेमाल 'कूटनीति और सामरिक प्रभाव के एक हथियार के तौर पर' कर रहा है; यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब चांद पर पहुंचने की इन दोनों देशों की होड़, और तेज हो गई है। अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष को लेकर चल रही होड़ में दोनों देशों का लक्ष्य आने वाले सालों में चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। जहां चीन ने अपनी पहली मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है, वहीं अमेरिका के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2028 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर वापस लाना, और 2030 तक वहां एक अंतरिक्ष सैन्य अड्डा बनाना शुरू करना है इससे इन दोनों महाशक्तियों के बीच कड़ी टक्कर शुरू हो गई है।

'सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' में एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन के हाउस फॉरेन अफेयर्स सब-कमेटी ऑन यूरोप की एक सुनवाई में दी जानकारी के मुताबिक, 'जैसे-जैसे देश मानकों के मामले में अमेरिका या चीन में से किसी एक के साथ जुड़ेंगे, तो जीतने वाला देश न सिर्फ तकनीक देगा, बल्कि वह उन शर्तों को भी तय करेगा, जिनके आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा। नेटवर्क आपस में काम करेंगे, लेकिन दुनिया को किस नजर से देखा जाएगा?' सुनवाई के दौरान फ्लोरिडा के रिपब्लिकन कांग्रेसी रैंडी फाइन के अनुसार, 'जब अंतरिक्ष की बात आती है, तो वह 'चीन को लेकर बहुत चिंतित हैं, जैसा कि मुझे पता है कि और भी कई लोग हैं। मुझे लगता है कि चीन खुद को हमारे साथ युद्ध की स्थिति में देखता है। यह भी कि हम अक्सर इसे उसी नजर से नहीं देखते।' दरअसल पिछले एक साल में अंतरिक्ष दौड़ में कई अहम घटनाक्रम देखने को मिले हैं; अमेरिका ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम का दूसरा सफल मिशन पूरा किया, वहीं चीन ने अपने 2030 के मून मिशन की तैयारी में कई अहम प्रगति की।

अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने इंसानों को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाया है। दूसरी तरफ चीन, भारत और पूर्व सोवियत संघ सहित अन्य देशों ने चांद की सतह पर रोबोटिक मिशन

उतारने में कामयाबी हासिल की। गत बुधवार को हुई इस सुनवाई का शीर्षक था, 'ऑर्बिट्स ऑफ इन्फ्लुएंस यूएस स्पेस सिक्योरिटी'। यह सुनवाई उसी दिन हुई, जिस दिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्टेमिस-टू के अंतरिक्ष यात्रियों की मेज़बानी की थी। इस कार्यक्रम में नासा मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। सुनवाई के दौरान, एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन का चीन पर आरोप था कि वह ग्लोबल साउथ में अपनी साझेदारियों का विस्तार करके अंतरिक्ष का इस्तेमाल अन्य देशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कर रहा है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्पेस पॉलिसी इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर स्कॉट पेस के मुताबिक, चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को मशहूर 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के जरिए आगे बढ़ा रहा है, जिसमें पार्टनर देशों को जोड़ने वाला एक बढ़ता हुआ स्पेस कंपोनेंट भी शामिल है। कैरी बिंगेन के खुलासे के मुताबिक, चीन ने 'ग्लोबल साउथ' कहे जाने वाले लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों के साथ समझौते किए हैं। बिंगेन के मुताबिक, 'वे स्पेस ग्राउंड एंटीना, ग्राउंड स्टेशन कमांड और कंट्रोल साइट लगा रहे हैं। यह बुनियादी टेक्नोलॉजी है जो उन ग्राउंड स्टेशनों और एंटीना को सरकारी सिस्टम या किसी कमर्शियल सिस्टम के साथ बातचीत करने में मदद करता है।' अमेरिकी एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन के मुताबिक, 'चीन, जहां एक तरफ अपना कमर्शियल स्पेस सेक्टर बना रहा है, वहीं उसका यह प्रोग्राम काफी हद तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है। इस सुनवाई में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच हुई स्पेस रेस का भी ज़िक्र हुआ, जब रूस, 'सोवियत संघ' के नाम से जाना जाता था।'

20वीं सदी का ज्यादातर हिस्सा मुकाबले में गुजर गया, लेकिन हाल के सालों में हालात बदल गए हैं। इस बारे में बिंगेन के विचार हैं कि जहां रूस अभी भी एक खतरा बना हुआ है, वहीं चीन एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरा है, जो किसी भी आधुनिक स्पेस प्रोग्राम के इतिहास में सबसे तेज़ तरक्की में से एक है। कैरी बिंगेन के अनुसार, 'स्पेस में नई ऊंचाइयां छूने की दौड़ जारी है- अमेरिका, चीन और रूस, मिलिट्री और सुरक्षा के क्षेत्रों में स्पेस में एक-दूसरे से लगातार मुकाबला कर रहे हैं।

देहरी पर न्याय की चलती फिरती चौपाल की दस्तक

डॉ. सुधीर कुमार

इतिहास गवाह है कि न्याय की सुगमता ही किसी शासन की सफलता की कसौटी होती है। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी 'न्याय की जंजीर' के जरिए यह संदेश दिया था कि फरियादी को दरबार तक आने की जरूरत नहीं, वह जंजीर खींचकर सीधे राजा तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है। आज के लोकतांत्रिक भारत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा 'न्याय रो साथी' वाहनों को हरी झंडी दिखाना उसी 'एक्सेस टू जस्टिस' का आधुनिक और तकनीकी अवतार है। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के उस विजन को साकार करती है, जहां न्याय केवल एक भव्य इमारत तक सीमित न रहकर, सचल वाहनों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति की दहलीज तक पहुंच रहा है। यह केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा इस पहल को हरी झंडी दिखाना उस विजन को धरातल पर उतारता है, जो केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का संकेत देते हैं। आज के दौर में, जब अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ है, तब वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) को न्याय व्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनाने की अपील महज एक सुझाव नहीं, बल्कि समय की मांग है। अकादमिक दृष्टि से देखें तो 'न्याय रो साथी' पहल विधि के 'प्रो-एक्टिव' स्वरूप को दर्शाती है। प्रसिद्ध विधिशास्त्री रोस्को पाउंड के 'सोशल इंजीनियरिंग' सिद्धांत के अनुसार, कानून का प्राथमिक कार्य समाज के प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन बनाना है। जब न्याय 'सचल' होकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के पास पहुंचता है, तो यह 'डिस्ट्रिब्यूटिव जस्टिस' के विचार को धरातल पर उतारता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल 'जीवन' नहीं, बल्कि 'त्वरित न्याय' और 'सम्मानजनक जीवन' की गारंटी देता है, जिसे अनुच्छेद 39ए (नि:शुल्क विधिक सहायता) धरातल पर उतारता है, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे।

इसी संवैधानिक वादे की भौतिक परिणति है-'न्याय रो साथी'। यह वाहन केवल एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक 'लीगल एम्बुलेंस' है, जो विवाद के 'नासूर' बनने से पहले ही मध्यस्थता के जरिए उसका 'कानूनी प्राथमिक उपचार' कर देती है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि 'न्याय तक पहुंच' एक अधिकार बना रहे, न कि कोई विशेषाधिकार। यह 'डिजिटल साक्षरता' और 'सचल न्याय' के समन्वय से ग्रामीण भारत में शोषण पर लगाम लगाने का एक सशक्त माध्यम है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वैकल्पिक विवाद समाधान को न्याय व्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनाने पर जो बल दिया है, वह वास्तव में भारतीय समाज में 'लीगल प्लुरलिज्म' की गहरी स्वीकृति है। भारत जैसे देश में, जहां पारंपरिक रूप से पंचायतों और मध्यस्थता की जड़ें ऐतिहासिक रूप से गहरी रही हैं, एडीआर उन प्राचीन पद्धतियों को एक आधुनिक संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है। यह पहल पारंपरिक मुकदमेबाजी की 'जीत-हार' वाली कठोर मानसिकता को 'संवाद और समाधान' में बदलकर समय, धन और संबंधों को टूटने से बचाता है। यदि छोटे दीवानी और शमनीय मामलों का निपटारा इसी मंच पर हो, तो उच्च न्यायपालिका के पास जटिल संवैधानिक और नीतिगत विषयों के लिए अधिक समय उपलब्ध होगा।

इन वाहनों की सबसे बड़ी शक्ति इनका तकनीक से लैस होना है। ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये 'डिजिटल डिवाइड' को पाटते हुए न्याय का एक 'मानवीय चेहरा' प्रस्तुत करते हैं। तकनीक का यह समावेशन केवल प्रक्रियात्मक सुगमता नहीं, बल्कि न्याय के 'संवैधानिक नैतिकता' के प्रति हमारे संकल्प को दर्शाता है। जब एक सुदूर गांव का व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी परामर्श पाता है, तो वह राज्य की न्यायप्रियता में अपना खोया हुआ विश्वास पुनर्जीवित करता है। यह 'लीगल ऑल्ट्रिज्म' (विधिक परोपकारिता) का वह स्वरूप है, जहां कानून की शुष्कता मानवीय संवेदनाओं के साथ मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करती है। न्याय की यह वैश्विक अवधारणा भारत को उन प्रगतिशील देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जहां 'एक्सेस टू जस्टिस' के मॉडल तेजी से बदल रहे हैं।

जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 'मोबाइल लीगल एड' सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच रही है, सिंगापुर 'एडीआर हब' बनकर मध्यस्थता को प्राथमिकता दे रहा है, और ब्रिटेन का 'स्मॉल क्लेम ट्रैक' बिना जटिलता के छोटे विवाद सुलझा रहा है; ठीक वैसे ही 'न्याय रो साथी' तकनीक और गतिशीलता के समन्वय से भारत में न्याय के नए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। यह व्यवस्था प्राचीन 'वट-वृक्ष' वाली न्याय-चौपालों का संवैधानिक और तकनीकी विस्तार है। इसे प्रभावी बनाने हेतु विधि विश्वविद्यालयों के 'लीगल एड क्लिनिक्स' को इन वाहनों से जोड़ना और ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। विधिक साक्षरता के लिए जटिल भाषा के बजाय स्थानीय बोलियों और पंचतंत्र व हितोपदेश की कथाओं का सहारा लेना चाहिए। यह पहल न्याय को ऊंची इमारतों से निकालकर सीधे 'जनता के द्वार' तक लाकर शक्ति का वास्तविक विकेंद्रीकरण करती है। अब समय 'तारीख-पर-तारीख' की सुस्त संस्कृति से निकलकर 'संवाद और समाधान' की ओर बढ़ने का है। जब न्याय स्वयं चलकर पीड़ित की देहरी तक पहुंचता है, तो राज्य की जन-कल्याणकारी छवि और अधिक प्रखर होती है। यह उस स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता कदम है, जहां अधिकारों के लिए किसी भी नागरिक को दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा।

पिकनिक पर जा रहे हैं तो टिफिन में ले जाएं ये डिशेस

स्कूल में अब बच्चों की ग्रीस्मकालीन छुटियां होने वाली हैं। ऐसे में बच्चे घर में बोर होने लगते हैं तो कहीं घुमने की जिद करते हैं। ऐसे में जब बच्चों को पिकनिक जैसास कुछ प्लान करें तो वहां इन्हें बाहर का कुछ खिलाने के बजाय घर से ही ऐसी डिशेस बनाकर ले जाएं जो बच्चों को पसंद आएं। क्योंकि ये छुट्टियां परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने का भी एक बेहतरीन अवसर है। क्योंकि इन छुट्टियों में लोग शहर की हलचल से दूर किसी पार्क, झील या हिल स्टेशन की ओर निकलते हैं और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं। पिकनिक का मजा तभी पूरा होता है जब आप स्वादिष्ट और हेल्दी लंच साथ लेकर जाएं। तैयार पैक लंच न केवल आपको बार-बार बाहर के खाने की चिंता से मुक्त करता है, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित रहता है। साथ ही ये आपकी यात्रा को व्यवस्थित और आरामदायक बनाता है।

सैंडविच

सैंडविच पिकनिक लंच का सबसे आसान और लोकप्रिय विकल्प है। आप ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीच में हरी सब्ज़ियां, पनीर, उबले अंडे, सलाद और हल्का सॉस डालें। सैंडविच को प्लास्टिक रैप या एयरटाइट कंटेनर में पैक करें, ताकि यह ताजा रहे। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयुक्त है और आसानी से खाने योग्य होता है।

स्नैक्स बॉक्स

अगर आपको हल्का और क्रिस्पी खाना पसंद है तो स्नैक्स बॉक्स बना सकते हैं। इसमें मूंगफली, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन और ड्राय फरूट्स डालें। नमकीन अगर घर पर बनी होगी तो ये ज्यादा बेहतर रहेगी। ये पेट भरने के लिए पर्याप्त है और लंबे समय तक बाहर रहने पर भी आसानी से खाया जा सकता है।

रैप्स या रोल्स

रैप्स या रोल्स पिकनिक के लिए बढ़िया विकल्प हैं क्योंकि इन्हें हाथों से आसानी से खाया जा सकता है। टॉर्टिला या पराठा लें और उसमें हरी सब्ज़ियां, ग्रिल्ड चिकन, पनीर या सलाद भरें। इन्हें एल्यूमीनियम फॉयल या एयरटाइट बैग में पैक करें ताकि यात्रा में यह खराब न हों। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ 30 मिनट में तैयार किया जा सकता है. इसे हरी चटनी और सलाद के साथ मिलाएं और इसकी गुडनेस का मजा लें।

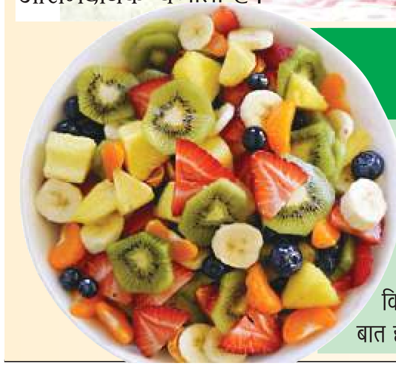

फ्रूट सलाद

फ्रूट सलाद हेल्दी और रिफ्रेशिंग विकल्प है। इसमें सेब, केला, अंगूर, अनानास, आम और संतरे जैसी फलियाँ डालें। ऊपर से थोड़ी नींबू का रस और शहद मिलाएं, ताकि सलाद ताज़ा और स्वादिष्ट रहे। ये पिकनिक में बच्चों के लिए विशेष रूप से अच्छा विकल्प है। फ्रूट सलाद के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखें की फल हमेशा ताजे ही प्रयोग करें।

समोसा

थोड़ी डिफरेंट चीज़ चाहते हैं तो समोसे पैक कर सकते हैं। समोसा बच्चों के लिए मजेदार और पसंदीदा विकल्प है। इन्हें बच्चों के साथ बड़े भी पसंद करते हैं और इन्हें बनाना भी आसान ह। इन्हें भी एयरटाइट कंटेनर में पैक करके ले जाएं।

हंसना मना है

पति-पत्नी दोनों मार्किट गए, वहां पति ने एक अनजान, लड़की से कहा हेलो! पत्नी गुस्से में -बताओ ये कौन थी? पति कुछ सोचकर- ओए चुप कर, अभी उसे भी बताना है की, तुम कौन हो!

पति- काम के लिए बाई रखे? पत्नी- नहीं चाहिए, पति- क्यों? पत्नी-तुम्हारी आदते मैं अच्छी तरह, जानती हूं भूल गए? पहले मैं भी बाई ही थी!

देवदास की तरह जान मत दो यारो, प्यार को लात मारो यारो, मेरी बात मानो यारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, रोज़ रात एक किंगफिशर मारो, और चैन से जिंदगी गुज़ारो..!

गर्लफ्रेंड-मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आये हो, पप्पू- चल पगली, कुछ भी हो मैं शादी तुमसे ही करूंगा.. आंटी से कहना वो मुझे भूल जाएं।

नजरे आज भी उस बेवकूफ को ढूंढ रही हैं, जिसने कहा था बुक के बीच में मोर पंख रखने से विद्या आती है।

प्रेमिका- तुम तो बस काम में लगे रहते हो! मेरी तो परवाह ही नहीं करते! प्रेमी- एक बात तुम गौर से सुन लो! प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते!

कहानी | मित्र-द्रोह का फल

हिम्मत नगर में दो पक्के दोस्त धर्मबुद्धि और पापबुद्धि रहा करते थे। एक दिन पापबुद्धि के मन में ख्याल आया कि क्यों न दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। उसने सोचा धर्मबुद्धि को भी साथ लेकर जाएगा, फिर लौटते समय वो धर्मबुद्धि से उसका पैसा किसी तरह से हड़प लेगा। वह धर्मबुद्धि को लेकर दूसरे शहर पहुंच गया। दोनों ने सामान को काफी अच्छी कीमत में बेचा। फिर दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगे। पापबुद्धि अपने दोस्त को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं, तो समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग जलने लगेंगे। ऐसे में हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। धर्मबुद्धि ने पापबुद्धि की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हां कर दी। पापबुद्धि ने गड्ढा खोदकर धन को एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद पापबुद्धि अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। एक दिन धर्मबुद्धि को पैसे की जरूरत पड़ी। तो पापबुद्धि से कहने लगा, मुझे पैसों की जरूरत है, जंगल से पैसे निकालकर ले आते हैं। पापबुद्धि राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही धर्मबुद्धि ने गड्ढा खोदा, तो वहां पैसा न देखकर चौंक गया। इतने में पापबुद्धि ने शोर मचाना शुरू कर दिया और धर्मबुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया। और पापबुद्धि न्यायालय पहुंचा। न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। पापबुद्धि ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली। पापबुद्धि पास के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की तो जंगल से आवाज आई, धर्मबुद्धि ने चोरी की है। धर्मबुद्धि ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई, उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए पापबुद्धि बाहर निकला और झुलसी हालात में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाशीध ने पापबुद्धि को फांसी की सजा सुना दी और धर्मबुद्धि को उसके पैसे दिलवा दिए।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

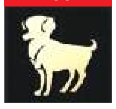

आय बनी रहेगी। व्यापार ठीक चलेगा। नौकरी में सहकर्मी विरोध कर सकते हैं। जोखिम व जमानत के कार्य टालें, धैर्य रखें। चोट व दुर्घटना से हानि संभव है।

तुला

व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। ऐश्वर्य के साधनों पर व्यय होगा। जल्दबाजी न करें।

वृषभ

नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। पिछले लंबे समय से रुके कार्य बनेंगे। प्रसन्नता रहेगी। दूसरों से अपेक्षा न करें। घर-परिवार की चिंता रहेगी। अज्ञात भय सताएगा।

वृश्चिक

प्रसन्नता रहेगी। भाग्य अनुकूल है। लाभ लें। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है।

मिथुन

रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। भूमि व भवन संबंधित कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में अनुकूलता रहेगी।

धनु

लाभ होगा। लाभ में कमी रह सकती है। नौकरी में कार्यभार रहेगा। आलस्य न करें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। यात्रा में कोई चीज भूलें नहीं।

कर्क

व्यापार ठीक चलेगा। निवेश में जल्दबाजी न करें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पारिवारिक जीवन सुख-शांति से बीतेगा। प्रसन्नता रहेगी। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे।

मकर

व्यापार में वृद्धि के योग हैं। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में चैन रहेगा। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। यात्रा लाभदायक रहेगी। कानूनी समस्या हो सकती है।

सिंह

व्यवसाय की गति धीमी रहेगी। आय बनी रहेगी। दूसरों को कार्य में हस्तक्षेप न करें। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। बेवजह दौड़धूप रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुम्भ

प्रसन्नता रहेगी। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। नौकरी में अधिकार बढ़ेंगे। आय में वृद्धि होगी। सुख के साधनों पर व्यय होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रमाद न करें।

कन्या

निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नए काम करने की इच्छा बनेगी। प्रसन्नता रहेगी। सामाजिक कार्य करने का मन बनेगा।

मीन

रुके कार्यों में गति आएगी। तंत्र-मंत्र में रुचि बढ़ेगी। सत्संग का लाभ मिलेगा। कानूनी सहयोग मिलेगा। लाभ में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा।

संजय दत्त की आखिरी सवाल की रिलीज डेट बदली, अब 15 को दस्तक देगी फिल्म

संजय दत्त इन दिनों अपनी आगामी फिल्म आखिरी सवाल को लेकर सुर्खियों में हैं। यह फिल्म आज यानि शुक्रवार 08 मई को रिलीज होनी थी। मगर, अब इसकी रिलीज डेट में बदलाव हो गया है। नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर को लेकर भी अपडेट आया है। यह फिल्म बेशक 08 मई को रिलीज नहीं हो रही है, मगर इसका ट्रेलर कल रिलीज हो रहा है।

फिल्म आखिरी सवाल के लिए दर्शकों को ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े दिन का और इंतजार करना होगा। यह फिल्म अब 15 मई 2026 को रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होने के चलते फिल्म तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई। अब सेंसर बोर्ड से इसे हरी झंडी मिल गई है, ऐसे में नई तारीख का एलान भी मेकर्स ने कर दिया है।

इंस्टाग्राम पोस्ट साझा कर मेकर्स ने नई रिलीज डेट की जानकारी दी है और साथ ही ट्रेलर पर भी अपडेट दिया है। इसमें लिखा है, कल, देश सच देखेगा। इंतजार खत्म हुआ। सबसे ज्यादा इंतजार वाला ट्रेलर कल आएगा। इस फिल्म को निखिल नंदा और संजय दत्त ने प्रोड्यूस किया है। वहीं, पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे और उज्जवल आनंद इसके को-प्रड्यूसर हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग ने संभाली है।

फिल्म आखिरी सवाल में संजय दत्त के अलावा, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, अमित साध, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में हैं। नमाशी चक्रवर्ती ने विक्की नाम के युवा विद्वान की भूमिका अदा की है। उनके गुर प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी का रोल संजय दत्त ने अदा किया है। इस फिल्म में आरएसएस के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। फिल्म में आरएसएस पर बैन, बाबरी विध्वंस जैसी कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र देखने को मिलेगा।

बॉलीवुड | परंपरा

हर फिल्म से जुड़ी कोई एक चीज अपने पास रखते हैं प्रभास

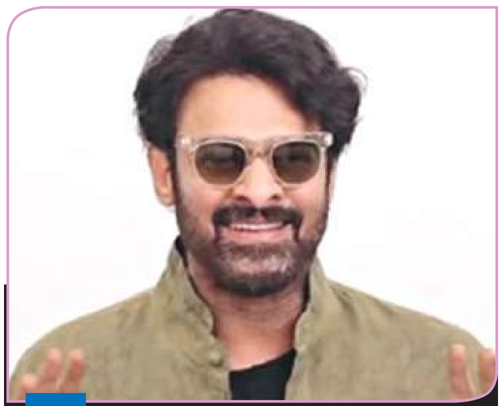

प्रभास भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उनके बारे में एक नई बात सामने आई है। इससे उनके निजी पहलू के बारे में पता चलता है। मनी कंट्रोल ने प्रभास के एक करीबी सूत्र के हवाले से लिखा है कि प्रभास की एक पुरानी आदत है। वह यह कि वह जिस भी फिल्म में काम करते हैं, उससे जुड़ी कोई एक खास चीज अपने घर ले आते हैं। इसे वह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और करियर के उस दौर की याद के तौर पर रखते हैं। सूत्र ने बताया कि यह परंपरा प्रभास के करियर की शुरुआत से ही उनके सफर का हिस्सा रही है। उन्होंने रिबेल से एक कोट, बाहुबली की मशहूर तलवार, साहो से एक बाइक और कार, सालार से उनकी खास बंदूक और कल्कि 2898 AD में इस्तेमाल हुई भविष्य की गाड़ी बुज्जी का एक हिस्सा अपने घर ले गए। उनके लिए ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी यादें हैं जो उन्हें उनके पूरे सफर की याद दिलाती रहेंगी। इन वर्षों में, प्रभास ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया है, जिनका लोगों पर गहरा असर पड़ा है। जो चीजें उन्होंने अपने पास रखी हैं, वे उनके इसी सफर को दिखाती हैं। प्रभास को बाहुबली से जबरदस्त शोहरत मिली है। यह फिल्म दुनियाभर में काफी मशहूर हुई है। इसके बावजूद प्रभास को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जाता है जो अपने काम और उससे जुड़ी यादों से गहराई से जुड़ा रहता है। अभिनेताओं का अपनी फिल्मों के कॉस्ट्यूम या चीजें अपने पास रखना कोई नई बात नहीं है। मगर प्रभास जिस तरह हर प्रोजेक्ट में लगातार ऐसा करते हैं, उससे यह साफ पता चलता है कि वह अपने फिल्मी सफर को कितना यादगार बनाना चाहते हैं और उसे कितने निजी तौर पर देखते हैं।

द वार्ड से रियलिटी शो की होस्टिंग में डेब्यू करेंगी रुबीना दिलैक

मूविंग इमेज स्टूडियोज ने अपने नए नॉन-फिक्शन शो 'द वार्ड' की घोषणा कर दी है, जिसे रुबीना दिलैक होस्ट करेंगी। यह एक रियलिटी शो है, जो मां बनने की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सच्चाइयों को बहुत सही तरीके से दिखाएगा।

इस शो में 10 गर्भवती महिलाएं 10 दिनों तक एक छत के नीचे रहेंगी। इस शो को मेटरनिटी वार्ड जैसी सेटिंग में फिल्माया गया है। यह शो, मां बनने की राह पर उनकी असली भावनाओं, विचारों और रिश्तों को ईमानदारी से दिखाएगा। ये महिलाएं अलग-अलग क्षेत्रों से आई हैं। वे धीरे-धीरे अपने निजी अनुभव साझा करेंगी, एक-दूसरे से जुड़ेंगी और बातें करेंगी।

इन बातों में शामिल होंगे- समाज की उम्मीदें, लड़कियों के प्रति भेदभाव, करियर की चाहत, परिवार में बदलते रिश्ते और मां बनने की चुनौतियां। रुबीना दिलैक सिर्फ होस्ट नहीं हैं, बल्कि वे सहानुभूति और समझ के साथ इन महिलाओं से जुड़ेंगी। खुद नई मां होने के नाते वे अपने अनुभव भी साझा करेंगी और सभी को सहारा देंगी। यह शो 15 मई को यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा। प्रतिभागियों के पति और परिवार वाले भी इस सफर का हिस्सा बनेंगे। वे साथ रहकर सीखेंगे, समझेंगे और रिश्तों को मजबूत करेंगे। शो में 24 घंटे कैमरा, डॉक्टरों की देखभाल और गहरी कहानी सुनाई जाएगी। इससे मातृत्व के सच्चे, कच्चे और दिल को छूने वाले पलों को दिखाया जाएगा।

रुबीना ने अपने सोशल मीडिया पर शो का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, मां बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा और भावनात्मक सफर रहा है। यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना मुश्किल भी कि कोई आपको पहले से तैयार नहीं कर सकता। 'द वार्ड' उन अनकही भावनाओं को दिखाता है, जिन्हें हम अंदर ही दबा लेते हैं। यह मेरा पहला रियलिटी शो है और मैं कह सकती हूं कि यह हर किसी के लिए भावनाओं का रोलरकोस्टर होगा।

देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जम्मू से कन्याकुमारी तक सीधी कनेक्टिविटी, जोड़ती है ये 12 राज्य

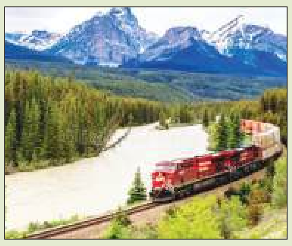

भारत में रेलवे सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। आज भी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी अनोखी ट्रेन भी है जो 12 राज्य को एक साथ जोड़ता है। Himsagar E&press भारत की उन खास ट्रेनों में शामिल है, जो अपने लंबे रूट और अनोखे सफर के लिए जानी जाती है। देश में कई ऐसे रेल मार्ग हैं, जहां यात्रा पूरी करने में 3 से 4 दिन तक का समय लग जाता है, लेकिन यह ट्रेन अपने आप में अलग पहचान रखती है क्योंकि यह एक साथ कई राज्यों को जोड़ती है। यह ट्रेन देश के उत्तर में स्थित Shri Mata Vaishno Devi Katra से चलकर दक्षिण के अंतिम छोर Kanyakumari तक जाती है। करीब 3790 किलोमीटर लंबा यह सफर इसे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में शामिल करता है। यही वजह है कि इसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक मजबूत कड़ी माना जाता है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपने पूरे रूट में 12 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। अपने इस लंबे सफर के दौरान यह लगभग 69 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है, जिससे लाखों यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव दक्षिण रेलवे के जिम्मे है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें अलग-अलग श्रेणियों के कोच लगाए गए हैं, जैसे एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर और जनरल डिब्बे हैं।आमतौर पर इस ट्रेन में करीब 20 कोच होते हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाते हैं। पूरे रूट को तय करने में इस ट्रेन को करीब 3 दिन (लगभग 70 से अधिक घंटे) का समय लगता है। इतना लंबा सफर तय करते हुए यह ट्रेन न केवल दूरी कम करती है, बल्कि भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी एक साथ जोड़ती है। कुल मिलाकर, Himsagar E&press सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक फैली एक अनोखी यात्रा है, जो देश के अलग-अलग हिस्सों को एक धागे में पिरोने का काम करती है।

अजब-गजब | अमेरिकियों ने जब पार्सल सेवा का उठाया अनोखा फायदा

जब डाक से भेजे जाते थे बच्चे! चिट्ठी की तरह पोता-पोती डिलीवर करता था डाकिया

आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और घर बैठे सामान मंगवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 साल पहले अमेरिका में लोग अपने बच्चों को भी डाक से भेज दिया करते थे? हां, ये बिल्कुल सच है। 1913 में जब अमेरिकी पोस्टल सर्विस ने पार्सल पोस्ट सेवा शुरू की, तो कुछ परिवारों ने इसका अनोखा फायदा उठाया। लोगों ने अपने बच्चों को चिट्ठी या पार्सल की तरह पैक करके दूसरे शहर या गांव भेजना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग अपने बच्चों को पोस्ट से दादी या नानी घर भेजते थे। इसका सबसे पहला रिकॉर्डेड मामला जनवरी 1913 का है, जब ओहियो के जेसी और मैथिल्डा बीगल दंपति ने अपने 8 महीने के बेटे जेम्स को अपनी दादी के घर भेजा था। बच्चे का वजन सिर्फ 10 पाउंड था। माता-पिता ने 15 सेंट के स्टांप लगाए और 50 डॉलर का बीमा भी करा लिया। रूरल मेल कैरियर ने बच्चे को सुरक्षित उसके दादी के घर पहुंचा दिया, जो सिर्फ एक मील दूर था।

बच्चों को पार्सल करने का सबसे प्रसिद्ध मामला 19 फरवरी 1914 का है। इडाहो की 5 वर्षीय शार्लोट मेय पियरस्टॉर्फ को उसके माता-पिता ने दादी के घर भेजा था। ग्रेंजविले से लेविस्टन तक की दूरी लगभग 73 मील थी। ट्रेन टिकट महंगा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने पार्सल पोस्ट का सहारा लिया। मेय के कोट पर 53 सेंट (कुछ रिपोर्ट्स में 32 सेंट) के स्टांप लगाए गए। उसे बेबी चिक के रूप में क्लासिफाई किया गया। मेय की मां के कजिन, जो रेलवे मेल क्लर्क थे, पूरे रास्ते उसके साथ रहे और उसे सुरक्षित दादी के घर पहुंचाया। मेय का वजन उस समय 48.5 पाउंड था, जो पार्सल पोस्ट की 50 पाउंड की लिमिट के अंदर था। पूरा सफर मेल कार में हुआ। वह डाकिया के साथ बैठी रही, खाना शेयर किया और बिना किसी समस्या के पहुंच गई। इस घटना पर बाद में बच्चों की किताब Mailing May भी लिखी गई। ये मामले दुर्लभ नहीं थे। 1913 से 1915 के बीच कम से कम 7-8 ऐसे दस्तावेजी मामले सामने आए।

एक अन्य मामले में 6 वर्षीय लड़की को 720 मील दूर फ्लोरिडा से वर्जीनिया भेजा गया था। एक 3 वर्षीय बच्ची को केंटकी में 40 मील दूर भेजा गया था। ज्यादातर मामलों में बच्चे रूरल एरिया से थे, जहां ट्रेन टिकट महंगा और परिवहन सीमित था। डाक विभाग पर भरोसा इतना था कि माता-पिता बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चों को डाकिया के हवाले कर देते थे। उस समय नियम सख्त नहीं थे। पार्सल पोस्ट के शुरुआती दिनों में यह स्पष्ट नहीं था कि इंसानों को नहीं भेजा जा सकता। लोग इसका फायदा उठाते रहे। बच्चे के कपड़ों पर स्टांप चिपकाए जाते, गले में या कोट पर एड्रेस का टैग लगाया जाता और डाकिया उन्हें ट्रेन या घोड़ागाड़ी से सही जगह पहुंचा देता। बच्चे ज्यादातर मेल क्लर्क के साथ रहते थे, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। लेकिन सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी उठने लगी। लोगों को डर था कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए या बच्चे खो ना जाएं। 1915 तक पोस्टमास्टर जनरल ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया कि मानव को मेल के जरिए नहीं भेजा जा सकता। इसके बाद यह प्रथा खत्म हो गई।

बम धमाकों पर पंजाब में नहीं रूक रहा सियासी घमासान

राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले- भाजपाइयों का इतिहास आईएसआई के साथ वाला

» पंजाब ब्लास्ट पर आप सांसद का बयान- भाजपा नफरत फैलाती है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बम धमाकों पर पंजाब में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा ने सीएम मान को मानहानि की नोटिस भेजी है। संजय सिंह ने पंजाब में हुए दो विस्फोटों को लेकर भाजपा की बयानबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 17 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए मोड़ विस्फोट की याद दिलाता है। संजय सिंह ने कहा कि तब भी अकाली दल और भाजपा की सरकार थी। उस मोड़ विस्फोट का भी कोई पता नहीं चला था। अब बंगाल चुनाव के तुरंत बाद भाजपा मिशन पंजाब की बात कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि यह वहां के अमन-चैन को बिगाड़ना, नफरत फैलाना और झगड़े कराना है। उन्होंने भाजपा पर आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाया।

सिंह ने पुलवामा विस्फोट में 350 किलो आरडीएक्स के स्रोत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह अभी तक पता नहीं चला है कि आरडीएक्स देश में कैसे आई। संजय सिंह ने पहलगाम घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए। इस पर ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। लेकिन सुरक्षा किसके आदेश पर हटाई गई, इसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है। सिंह ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर बीते तीन वर्षों से जल रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भाजपा को इसकी कोई चिंता नहीं है। वे देश का माहौल खराब और बिगड़ा हुआ चाहते हैं। उन्होंने बंगाल में चुनाव जीतने के बाद हुई हिंसा का भी उल्लेख किया। बीते दिन मुख्यमंत्री के दावेदार सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या हुई। इससे पहले तृणमूल के लोगों पर हमले हुए और उनके कार्यालय जलाए गए। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव की राजनीति की बात करते हैं। लेकिन भाजपा पंजाब में भी यही सब करना चाहती है। उन्होंने देश और पंजाब के लोगों को ऐसी घृणा फैलाने वाली पार्टी से सावधान रहने की सलाह दी। सिंह ने याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का एक सदस्य लश्कर-ए-तैबा से जुड़ा था।

मणिपुर और बंगाल में हिंसा पर पीएम को चिंता नहीं

मान ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा गिराई : चुघ

मुख्यमंत्री के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा नेता चुघ ने कहा कि मान ने बिना किसी सबूत के भाजपा पर बम धमाकों में संलिप्तता का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। चुघ ने पत्रकारों से कहा कि इसीलिए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि, झूठी सूचना फैलाने और जन अशांति भड़काने के प्रयास के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मान का बयान उनके अपने डीजीपी के रुख के बिल्कुल विपरीत है। पंजाब पुलिस जहां पाकिस्तान की आईएसआई और विदेशी नेटवर्क की संलिप्तता की ओर इशारा कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं। उन्होंने पूछा कि सवाल सीधा सा है- क्या मुख्यमंत्री पंजाब की सुरक्षा कर रहे हैं, या वे राष्ट्रविरोधी ताकतों को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं?

भाजपा ने सीएम को भेजी मानहानि की नोटिस

भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जालंधर और अमृतसर बम धमाकों के लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराने पर मानहानि का नोटिस भेजा है। भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने मान से सबूत पेश करने या इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे बयान राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हैं और सामाजिक अशांति पैदा कर सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को जालंधर और अमृतसर में हुए दोहरे बम धमाकों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने वाले उनके बयान के लिए मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा और उनसे अपने दावे का सबूत देने या पद से इस्तीफा देने को कहा। मंगलवार रात पंजाब में सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास हुए दो सिलसिलेवार धमाकों से दहशत फैल गई और विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भगवंत मान सरकार को निशाना बनाया। बुधवार को मान ने दोनों धमाकों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी इसी तरह कर रही है। पहला विस्फोट जालंधर में सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय के बाहर रात करीब 8 बजे हुआ, जबकि दूसरा विस्फोट अमृतसर के खासा में सेना शिविर के पास रात करीब 11 बजे हुआ।

एसीबी का दुरुपयोग कर रही भाजपा : गहलोत

» राजस्थान में महेश जोशी की गिरफ्तारी पर दी प्रतिक्रिया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी द्वारा पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर कड़ी आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। गहलोत ने कहा कि महेश जोशी की गिरफ्तारी अनैतिक, दुर्भावनापूर्ण और कानून के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार किसी भी आरोपी को पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर ही गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके बावजूद एसीबी ने बिना किसी नोटिस या पूर्व पूछताछ के सुबह 5 बजे सीधे गिरफ्तारी की कार्रवाई की, जिससे सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

गहलोत ने कहा कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए लेकिन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में वास्तविक कार्रवाई करने के बजाय राजनीतिक आधार पर एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि गांव-ढाणी से लेकर राजधानी तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जनता परेशान है लेकिन सरकार विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने में जुटी हुई है। महेश जोशी ने पहले ईडी की कार्रवाई के दौरान भी पूरा सहयोग किया था।

सवालों के घेरे में लखनऊ स्वच्छता अभियान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी की सफाई व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर निगम की कार्यदाई संस्था लखनऊ स्वच्छ अभियान पर लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, लेकिन कार्रवाई केवल जुर्माने और चेतावनी तक सीमित नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि महापौर सुषमा खर्कवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार और संसदीय क्षेत्र के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के निरीक्षणों में भी शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र मिला हो जहां सफाई व्यवस्था संतोषजनक दिखाई दी हो। कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगी, कार्यदाई संस्था पर जुर्माना भी लगाया गया और जोनल अधिकारियों के वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की बातें भी सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर हालात में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा।

जब कार्यदाई संस्था की कार्यशैली शुरुआत से ही सवालों में थी तो आखिर इतनी जल्दबाजी में उसे लगातार बड़े स्तर पर काम क्यों सौंपा गया। चर्चा यह भी है कि कई पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों में इसी कंपनी से सफाई कार्य कराने के लिए लिखित सहमति तक दे दी, जिसके बाद संस्था का दायरा तेजी से बढ़ता चला गया। अब जब लगातार शिकायतें और निरीक्षणों में खामियां सामने आ रही हैं तो नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। कि हर निरीक्षण में गंदगी मिलने और जुर्माने की कार्रवाई होने के बावजूद यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा, तो केवल कार्रवाई दिखाने भर से काम नहीं चलेगा। जरूरत जवाबदेही तय करने और स्थायी समाधान की है।

» हर दौरे में मिली गंदगी, फिर भी काम देने में कमी नहीं

» कई पार्षदों ने दी लिखित सहमति

महापौर ने कही थी तीन महीने ट्रायल के बाद निर्णय लिया जाएगा

महापौर सुषमा खर्कवाल ने शुरुआती दौर में कहा था कि कंपनी को पहले तीन महीने ट्रायल पर रखा जाएगा और उसके प्रदर्शन के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हालात इसके उलट दिखाई दिए। ट्रायल की अवधि पूरी होने से पहले ही कंपनी को तय सीमा से कहीं अधिक कार्यक्षेत्र सौंप दिया गया।

गर्मी का इलाज, जेब में रखो प्याज पर कांग्रेस का तंज

» जयराम रमेश ने दिल्ली सरकार किया वार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के लू अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के एक मंत्री ने पहले ही गर्मी का इलाज, जेब में प्याज़ रखो की लू कार्य योजना की घोषणा कर दी है। जयराम रमेश का यह तंज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस पुराने नुस्खे पर था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे गर्मी के चरम मौसम में अपनी जेब में प्याज रखते हैं ताकि गर्मी से राहत पा सकें।

रमेश ने कहा कि सीएम ने गर्मी से जंग, दिल्ली सरकार के संग के नारे के साथ देश की राजधानी के लिए एक हीट एक्शन प्लान की घोषणा की है। दरअसल, उनके भाजपा सहयोगी और मोदी सरकार के एक मंत्री ने पहले ही गर्मी का इलाज, जेब में प्याज रखो के नारे के साथ हीट एक्शन प्लान शुरू कर दिया था।

घर में 5 मैचों बाद लखनऊ की पहली जीत

» मिचेल मार्श के बाद प्रिंस और शाहबाज चमके, आरसीबी को 9 रन से हराया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने गुरवार को खेले गए आईपीएल मुकाबले में आरसीबी को नौ रन से हरा दिया। इकाना स्टेडियम में बारिश से प्रभावित इस मुकाबले को 19-19 ओवर का किया गया। डकवर्थ-लुईस डीएलएस नियम के तहत आरसीबी को 213 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, लेकिन टीम 19 ओवर में छह विकेट पर 203 रन ही बना सकी। एलएसजी की यह मौजूदा सीजन में तीसरी जीत रही, जबकि आरसीबी को चौथी हार झेलनी पड़ी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही।

दो विकेट महज नौ रन पर गिरने के बाद पाटीदार और देवदत्त ने तीसरे विकेट के लिए 95 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। हालांकि, इसके बाद आरसीबी लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही। हलांकि निचले क्रम में टिम डेविड और क्रूणाल पांड्या ने अच्छी पारियां खेलीं। इसके बावजूद आरसीबी लक्ष्य से नौ रन दूर रह गई।

प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट झटके। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए एलएसजी ने निर्धारित 19 ओवर में तीन विकेट खोकर 209 रन बनाए। मिचेल मार्श ने 111 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने कुलकर्णी के साथ पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े। इसके बाद निकोलस पूरन ने 38 रन की तेज पारी खेली और मार्श के साथ दूसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की। अंतिम ओवरों में ऋषभ पंत ने 10 गेंदों में नाबाद 32 रन ठोककर टीम को 200 के पार पहुंचाया। आरसीबी की ओर से जोश हेजलवुड, क्रूणाल पांड्या और रसिख सलाम को एक-एक विकेट मिला।

क्रिकेटर्स से मिल रहे संदिग्ध लोग, एसीएसयू ने जताई चिंता

मुंबई। आईपीएल की भ्रष्टाचार रोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने मौजूदा सत्र के दौरान टीम डगआउट, बसों, होटलों और खिलाड़ियों एवं मैच अधिकारियों के क्षेत्र में बिना इजाजत लोगों की मौजूदगी पर चिंता जताई है जिसके बाद बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी के लिए अपने मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को और सख्त कर दिया है। अनजान लोगों के प्रतिबंधित स्थानों पर मौजूद रहने की वजह से स्पॉट फिक्सिंग का खतरा भी बढ़ गया है। आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने इस बात की पुष्टि की कि एसीएसयू ने इस मामले पर बीसीसीआई को एक रिपोर्ट सौंपी है। भ्रष्टाचार रोधी इकाई द्वारा बताई गई कमियों पर रोशनी डालते हुए धूमल ने कहा कि बोर्ड इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। एसीएसयू ने कुछ कमियों की ओर इशारा किया है और एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि आईपीएल मैचों के दौरान डगआउट, टीम बस और टीम होटल में बिना इजाजत लोग देखे गए हैं। यह संकेत देते हुए कि जल्द ही और भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे, धूमल ने कहा कि फ्रेंचाइजियों को पहले से तय नियमों का पालन करने की याद दिलाई जाएगी।

बंगाल में नहीं थम रही चुनाव के बाद हिंसा

हावड़ा के शिबपुर में कई बम धमाके, भाजपा व टीएमसी में झड़प जारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित शिबपुर में देसी बम विस्फोटों ने चुनावी हिंसा को और भड़का दिया है, जिसमें कथित तौर पर भाजपा नेता को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और भारी पुलिस बल तैनात है।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित शिबपुर झुग्गी बस्ती में गुरुवार को कई देसी बमों के विस्फोट के बाद तनाव का माहौल छा गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और निवासियों में अफरा-तफरी और चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोटों के

कारण ईंटें हवा में उड़ने लगीं और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को भारी संख्या में मौके पर पहुंचना पड़ा और त्वरित कार्रवाई बल (आरपीएफ) के जवानों ने शांति बहाल करने में मदद की।

टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी, चोर टीएमसी चोर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार के बाद राज्य की राजनीतिक तपिश अब विमानों के भीतर भी महसूस की जाने लगी है। कृष्णानगर से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि इंडिगो की एक फ्लाइट में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन पर तीखे व्यक्तिगत हमले किए गए। कृष्णानगर से लोकसभा सांसद मोइत्रा ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट पर कुछ वीडियो शेयर किए, जिनमें कुछ लोगों को चोर, चोर टीएमसी चोर, तृणमूल ईर शोब चोर और जय श्री राम जैसे नारे लगाते हुए सुना जा सकता है।

नागरिकों का गुस्सा नहीं विमान में उनकी सुरक्षा का उल्लंघन : मोइत्रा

महुआ मोइत्रा ने इसे नागरिकों का गुस्सा नहीं बताया और इसे एक परेशानी कहा, जिसने विमान में उनकी सुरक्षा का उल्लंघन किया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ अपने सख्त रुख़ के लिए जानी जाने वाली टीएमसी नेता ने इंडिगो से इन लोगों के नाम सार्वजनिक करने और उन्हें नो फ़्लाई लिस्ट में डालने को भी कहा, साथ ही उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को भी टैग किया। मोइत्रा ने अपनी एक पोस्ट में कहा यह बीजेपी की संस्कृति है। किसी को हैरानी क्यों हो रही है? मैंने इसे नज़रअंदाज़ किया और हवाई अड्डे से अपनी

बैठक में चली गई। फिर लोगों ने मुझे वह वीडियो भेजा जिसे संघी लोग वायरल कर रहे थे। तभी मैंने इस पर आवाज़ उठाई।

वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के बराबर नहीं मानेंगे : असदुद्दीन ओवैसी

एआईएमआईएम चीफ बोले-भारत मां नहीं, हम भारत के लोग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान वैधानिक दर्जा दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एक देवी को समर्पित है। एक लंबे-चौड़े एक्स पोस्ट में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि देश देवता या देवी के नाम पर नहीं चलता और यह किसी देवी या देवता का है भी नहीं।

ओवैसी ने लिखा है, जन गण मन भारत और उसके लोगों का गुणगान है, न कि

किसी खास धर्म का। धर्म और देश समान नहीं है। जिस व्यक्ति ने वंदे मातरम् लिखा, उनकी ब्रिटिश राज के प्रति सहानुभूति थी और मुसलमानों से नफरत करते थे। नेताजी बोस, गांधी, नेहरू और टैगोर सबने इसे खारिज किया। भारत के संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग से शुरू होती है, भारत मां से नहीं। यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वादा करता है। संविधान का पहला प्रावधान, अनुच्छेद 1 में इंडिया, जो कि भारत है, को राज्यों का एक संघ बताया गया है।

केरल में सीएम की रेस में केसी वेणुगोपाल सबसे आगे

पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक, अजय माकन देंगे कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट, महाराष्ट्र प्रभारी चेन्निथला पर भी चर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। केरल में सीएम की रेस में केसी वेणुगोपाल सबसे आगे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ज्यादातर विधायकों ने केसी वेणुगोपाल का नाम लिया है। पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक, अजय माकन थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को रिपोर्ट देने वाले हैं।

सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए दो वरिष्ठ नेताओं के नाम तय कर लिए गए हैं। इन दो नामों में से एक नाम अलाप्पुझा से लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल का है, जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं। वेणुगोपाल नायर समुदाय से हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं।

वेणुगोपाल ने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

63 वर्षीय वेणुगोपाल ने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए, सूत्रों के अनुसार, उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, यह गांधी पर निर्भर करेगा। रमेश चेन्निथला भी अगले मुख्यमंत्री बनने के संभावित दावेदारों में से एक हैं। वेणुगोपाल की तरह चेन्निथला भी नायर समुदाय से आते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में चेन्निथला केरल के गृह मंत्री और विपक्ष के नेता रह चुके हैं। इसके अलावा, वे कांग्रेस की केरल इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

चेन्निथला एक कुशल संगठनवादी

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी चेन्निथला को एक कुशल संगठनवादी माना जाता है। इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि चार बार सांसद रह चुके चेन्निथला को केरल का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाता है या नहीं। कांग्रेस द्वारा रविवार तक अगले मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है, क्योंकि पार्टी के नेता और विधायक एआईसीसी पर्यवेक्षकों को अपने विचार बता चुके हैं। वट्टियूरकावु से विजयी वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि मैंने अपनी राय दे दी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसला रविवार तक पता चल जाएगा।

फिर पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट

अमेरिकी सेना ने ईरान के दो बंदरगाहों पर किया हमला, ट्रंप ने तेहरान को दी चेतावनी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

तेहरान। अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक महत्व वाले केशम बंदरगाह और बंदर अब्बास पर हमले किए हैं। रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए इन हमलों की जानकारी दी है ईरानी मीडिया ने इन इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनने की पुष्टि की है, हालांकि हमलों की पूर्ण स्वतंत्र पुष्टि अभी लंबित है।

ये हमले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी तनाव के बीच हुए हैं, जहां अमेरिका ईरानी नावों और जहाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने इन घटनाओं को दुश्मन ड्रोनों से जोड़ा है। स्थिति तेजी से विकसित हो रही है और दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता भी चल रही है। वैश्विक तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति को बड़ा झटका लगा है।

अमेरिकी संघीय व्यापार अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 1० प्रतिशत वैश्विक आयात शुल्क को खारिज करते हुए कहा कि 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 का गलत इस्तेमाल किया गया अमेरिकी कोर्ट

ईरानी हमलावरों को भारी क्षति : ट्रंप

ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी कि यदि वह जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसके खिलाफ और भी कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि तीन विश्व स्तरीय अमेरिकी विध्वंसक पोत अभी-अभी भारी गोलाबारी के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य से सफलतापूर्वक निकल गए। आगे कहा कि तीनों विध्वंसक पोतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी क्षति हुई। वे कई छोटी नौकाओं के साथ पूरी तरह नष्ट हो गए, जिनका उपयोग उनकी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी नौसेना की जगह लेने के लिए किया जा रहा है।

ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 2-1 के फैसले में कहा कि ट्रंप प्रशासन 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का इस्तेमाल व्यापक व्यापार घाटे और चालू खाता घाटे के आधार पर नहीं कर सकता। अदालत के मुताबिक, यह कानून 197० के दशक की विशेष बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए बनाया गया था, न कि आधुनिक दौर के सामान्य व्यापार घाटे के लिए। जज मार्क ए. बार्नेट और क्लेयर आर. केली ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप की घोषणा यह साबित करने में विफल रही कि कानून के जरिए आवश्यक शर्तें पूरी हुई हैं।

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में ये टैरिफ लगाए थे। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति को इतनी व्यापक व्याख्या की अनुमति दे दी जाए, तो उन्हें लगभग असीमित टैरिफ लगाने की शक्ति मिल जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संवैधानिक सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि टैरिफ और व्यापार नीति तय करने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है।

बिहार में नौकरी मांगने वालों को मिली लाठियां, कई अभ्यर्थी चोटिल

शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के विज्ञापन जारी करने की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

राजधानी के जेपी गोलंबर पर बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया। इस दौरान कई छात्रों को चोटें आई हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि टीआरई-4 के लिए आयोग लगातार झूठ बोल रहा है। 13 लाख से अधिक छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। बार-बार विज्ञापन जारी करने के लिए नई तिथि बताई जा रही है। साल 2024 से अधियाचना मिलने की बात की जा रही है। हाल ही में परीक्षा नियंत्रक ने कहा था कि 19 अप्रैल को विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 25 या 26 अप्रैल से फार्म भरना शुरू हो जाएगा। आठ मई तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसी को लेकर हम आज

पटना जाम करने पहुंचे।

गौरतलब है कि टीआरई-4 में कुल चार विभागों में 46,882 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ये बहाली होंगी। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पद हैं, जिसमें माध्यमिक (कक्षा 9-1०) के 9०82 और उच्च माध्यमिक (11-12) के 16,774 रिक्तियों को भरा जाएगा। प्राथमिक (1-5) में 1०,778 और मध्य विद्यालय (6-8) में 8,583 पदों पर बहाली की जाएगी। 22 से 27 सितंबर के बीच परीक्षा के आयोजन की संभावना है।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। **विधि सलाहकार**: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा**
द्वारा **आस्था प्रिंटर्स**, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **संपादक- संजय शर्मा**